

Regional Aspirations

In this chapter...

In the first chapter of this book we studied the process of 'nation-building' in the first decade after Independence. But nation-building is not something that can be accomplished once and for all times to come. In the course of time new challenges came up. Some of the old problems had never been fully resolved. As democratic experiment unfolded, people from different regions began to express their aspirations for autonomy.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस अध्याय में...

आज़ादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया चली। हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था। लेकिन राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती। वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियाँ आई। कुछ पुरानी समस्याएँ ऐसी थीं कि उनका समाधान पूरी तरह से न हो सका था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे-जैसे हम बढ़े, वैसे-वैसे अलग-अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई।

Regional Aspirations

Sometimes these aspirations were expressed outside the framework of the Indian union. These involved long struggles and often aggressive and armed assertions by the people.

This new challenge came to the fore in the 1980s, as the Janata experiment came to an end and there was some political stability at the centre. This decade will be remembered for some major conflicts and accords in the various regions of the country, especially in Assam, the Punjab, Mizoram and the developments in Jammu and Kashmir.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

कभी-कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढाँचे के हदों को पार करके भी हुई। स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी-कभार हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खिंचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर-कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम साँसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी-बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू-कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े।

Regional Aspirations

In this chapter we study these cases so as to ask some general questions.

- **Which factors contribute to the tensions arising out of regional aspirations?**
- **How has the Indian state responded to these tensions and challenges?**
- **What kind of difficulties are faced in balancing democratic rights and national unity?**
- **What are the lessons here for achieving unity with diversity in a democracy?**

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सकें:

- क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है?
- भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए?
- लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं?
- लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है?

Region and the Nation

1980s may be seen as a period of rising regional aspirations for autonomy, often outside the framework of the Indian Union. These movements frequently involved armed assertions by the people, their repression by the government, and a collapse of the political and electoral processes. It is also not surprising that most of these struggles were long drawn and concluded in negotiated settlements or accords between the central government and the groups leading the movement for autonomy.

क्षेत्र और राष्ट्र

1980 के दशक को स्वायत्तता की माँग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की माँग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी माँग के पक्ष में हथियार उठाए; सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की माँग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े।

Regional Aspirations

The accords were reached after a process of dialogue that aimed to settle contentious issues within the constitutional framework. Yet the journey to the accord was always tumultuous and often violent.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल, समझौते तक पहुँचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब-तब हिंसा के स्वर उभरे।

Regional Aspirations

Indian approach

In studying the Indian Constitution and the process of nation-building we have repeatedly come across one basic principle of the Indian approach to diversity – the Indian nation shall not deny the rights of different regions and linguistic groups to retain their own culture. We decided to live a united social life without losing the distinctiveness of the numerous cultures that constituted it. Indian nationalism sought to balance the principles of unity and diversity.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

भारत सरकार का नज़रिया

राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नजरों से बार-बार गुजरी है : भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषायी समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बँधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था, जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है।

Regional Aspirations

The nation would not mean the negation of the region. In this sense the Indian approach was very different from the one adopted in many European countries where they saw cultural diversity as a threat to the nation.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया।

Regional Aspirations

India adopted a democratic approach to the question of diversity. Democracy allows the political expressions of regional aspirations and does not look upon them as anti-national. Besides, democratic politics allows parties and groups to address the people on the basis of their regional identity, aspiration and specific regional problems. Thus, in the course of democratic politics, regional aspirations get strengthened. At the same time, democratic politics also means that regional issues and problems will receive adequate attention and accommodation in the policy making process.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र-विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति-निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाएगी।

Regional Aspirations

Such an arrangement may sometimes lead to tensions and problems. Sometimes, the concern for national unity may overshadow the regional needs and aspirations. At other times a concern for region alone may blind us to the larger needs of the nation. Therefore, political conflicts over issues of power of the regions, their rights and their separate existence are common to nations that want to respect diversity while trying to forge and retain unity.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

एसी व्यवस्था में कभी-कभी तनाव या परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़ें। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताओं से आंखें मूँद लें। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है।

Regional Aspirations

Areas of tension

In the first chapter you have seen how immediately after Independence our nation had to cope with many difficult issues like Partition, displacement, integration of Princely States, reorganisation of states and so on. Many observers, both within the country and from outside, had predicted that India as one unified country cannot last long. Soon after Independence, the issue of Jammu and Kashmir came up. It was not only a conflict between India and Pakistan.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

तनाव के दायरे

आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देसी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ़ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था।

Regional Aspirations

More than that, it was a question of the political aspirations of the people of Kashmir valley. Similarly, in some parts of the north-east, there was no consensus about being a part of India. First Nagaland and then Mizoram witnessed strong movements demanding separation from India. In the south, some groups from the Dravid movement briefly toyed with the idea of a separate country.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नगालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की माँग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठायी थी।

Regional Aspirations

These events were followed by mass agitations in many parts for the formation of linguistic States. Today's Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat were among the regions affected by these agitations. In some parts of southern India, particularly Tamil Nadu, there were protests against making Hindi the official national language of the country. In the north, there were strong pro-Hindi agitations demanding that Hindi be made the official language immediately.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की माँग करते हुए जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों – खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध-आंदोलन चला।

Regional Aspirations

From the late 1950s, people speaking the Punjabi language started agitating for a separate State for themselves. This demand was finally accepted and the States of Punjab and Haryana were created in 1966. Later, the States of Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand were created. Thus the challenge of diversity was met by redrawing the internal boundaries of the country.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

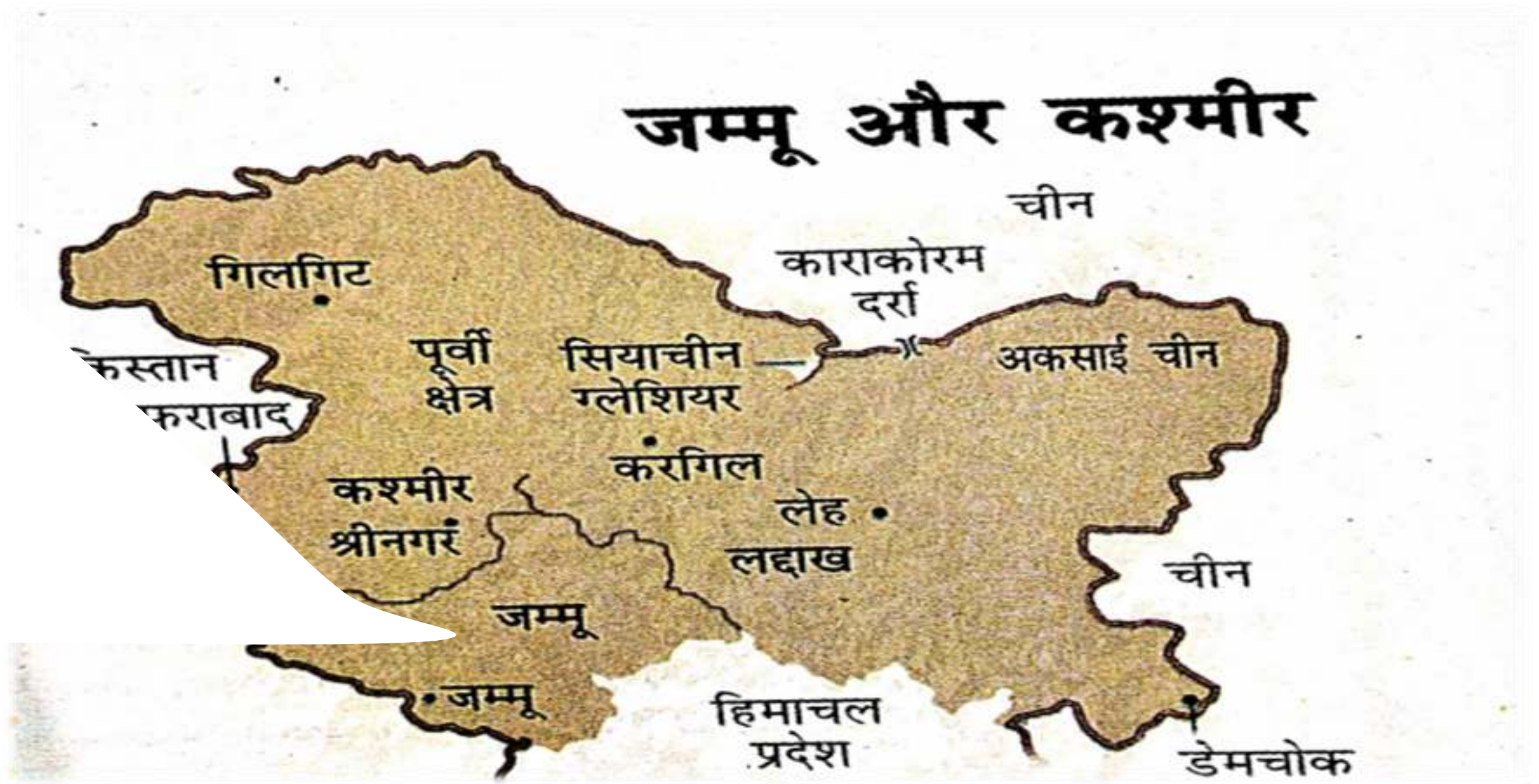
1950 के दशक के उत्तरार्द्ध से पंजाबी-भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उनकी माँग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया।

Regional Aspirations

Yet this did not lead to resolution of all problems and for all times. In some regions, like Kashmir and Nagaland, the challenge was so complex that it could not be resolved in the first phase of nation-building. Besides, new challenges came up in States like Punjab, Assam and Mizoram. Let us study these cases in some detail. In this process let us also go back to some of the earlier instances of difficulties of nation building. The successes and failures in these cases are instructive not merely for a study of our past, but also for an understanding of India's future.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

बहरहाल, इन प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानी का हमेशा के लिए हल निकल आया। कश्मीर और नगालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ इतनी विकट और जटिल थीं कि राष्ट्र-निर्माण के पहले दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियाँ उभरीं। आइए, हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ-साथ राष्ट्र-निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उनके उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए एक जरूरी प्रस्थान-बिंदु नहीं बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए भी एक जरूरी सबक है।



नोट: यह नक्शा किसी पैमाने के हिसाब से बनाया गया भारत का मानचित्र नहीं है। इसमें दिखाई गई भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को प्रामाणिक सीमा रेखा न माना जाए।

Regional Aspirations

Jammu and Kashmir You may have heard about the violence in Jammu and Kashmir (J&K). This has resulted in the loss of many lives and the displacement of many families. The 'Kashmir issue' is always seen as a major issue between India and Pakistan. But the political situation in the State has many dimensions.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

जम्मू एवं कश्मीर आपने जम्मू एवं कश्मीर में जारी हिंसा के बारे में सुना होगा। इसके परिणामस्वरूप अनेक लोगों की जान गई और कई परिवारों का विस्थापन हुआ। 'कश्मीर मुद्दा' भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन इस राज्य की राजनीतिक स्थिति के बहुत से आयाम हैं।

Regional Aspirations

Jammu and Kashmir comprises three social and political regions: Jammu, Kashmir and Ladakh. The heart of the Kashmir region is the Kashmir valley; the people are Kashmiri speaking and mostly Muslim with a small Kashmiri speaking Hindu minority. Jammu region is a mix of foothills and plains, of Hindus, Muslims and Sikhs and speakers of various languages. The Ladakh region is mountainous, has very little population which is equally divided between Buddhists and Muslims.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

जम्मू एवं कश्मीर में तीन राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं – जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। कश्मीरी बोली बोलने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं। बहरहाल, कश्मीरी-भाषी लोगों में अल्पसंख्यक हिंदू भी शामिल हैं। जम्मू क्षेत्र पहाड़ी तलहटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख यानी कई धर्म और भाषाओं के लोग रहते हैं। लद्दाख पर्वतीय इलाका है, जहां बौद्ध एवं मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन यह आबादी बहुत कम है।

Regional Aspirations

The 'Kashmir issue' is not just a dispute between India and Pakistan. This issue has external and internal dimensions. It involves the issue of Kashmiri identity known as Kashmiriyat and the aspirations of the people of J&K for political autonomy.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

‘कश्मीर मुद्दा’ भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ विवाद भर नहीं है। इस मुद्दे के कुछ बाहरी तो कुछ भीतरी पहलू हैं। इसमें कश्मीरी पहचान का सवाल जिसे कश्मीरियत के रूप में जाना जाता है, शामिल है। इसके साथ ही साथ जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्वायत्तता का मसला भी इसी से जुड़ा हुआ है।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Roots of the problem

Before 1947, Jammu and Kashmir (J&K) was a Princely State. Its Hindu ruler, Hari Singh, did not want to merge with India and tried to negotiate with India and Pakistan to have an independent status for his state. The Pakistani leaders thought the Kashmir region 'belonged' to Pakistan, since majority population of the State was Muslim. But this is not how the people themselves saw it – they thought of themselves as Kashmiris above all.

समस्या की जड़ें

1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। इसके हिंदू शासक हरि सिंह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर, पाकिस्तान से संबद्ध है, क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। बहरहाल यहाँ के लोग स्थिति को अलग नज़रिए से देखते थे। वे अपने को कश्मीरी सबसे पहले, कुछ और बाद में मानते थे।

Regional Aspirations

The popular movement in the State, led by Sheikh Abdullah of the National Conference, wanted to get rid of the Maharaja, but was against joining Pakistan. The National Conference was a secular organisation and had a long association with the Congress. Sheikh Abdullah was a personal friend of some of the leading nationalist leaders including Nehru.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

राज्य में नेशनल कांफ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें, लेकिन वे पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ़ थे। नेशनल कांफ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसका कांग्रेस के साथ काफी समय तक गठबंधन रहा। राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। इनमें नेहरू भी शामिल हैं।

Regional Aspirations

In October 1947, Pakistan sent tribal infiltrators from its side to capture Kashmir. This forced the Maharaja to ask for Indian military help. India extended the military support and drove back the infiltrators from Kashmir valley, but only after the Maharaja had signed an 'Instrument of Accession' with the Government of India. It was also agreed that once the situation normalised, the views of the people of J&K will be ascertained about their future.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ़ से कश्मीर पर कब्जा करने भेजा। ऐसे में कश्मीर के महाराजा भारतीय सेना से मदद माँगने को मजबूर हुए। भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ा। इससे पहले भारत सरकार ने महाराजा से भारत संघ में विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करा लिए। इस पर भी सहमति जताई गई कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा होगा।

Regional Aspirations

Sheikh Abdullah took over as the Prime Minister of the State of J&K (the head of the government in the State was then called Prime Minister) in March 1948. India agreed to maintain the autonomy of Jammu and Kashmir.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने (राज्य में सरकार के मुखिया को तब प्रधानमंत्री कहा जाता था)। भारत, जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इसे संविधान में धारा 370 का प्रावधान करके संवैधानिक दर्जा दिया गया।

Regional Aspirations

External and internal disputes

Since then, the politics of Jammu and Kashmir always remained controversial and conflict ridden both for external and internal reasons. Externally, Pakistan has always claimed that Kashmir valley should be part of Pakistan. As we noted above, Pakistan sponsored a tribal invasion of the State in 1947, as a consequence of which one part of the State came under Pakistani control.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

बाहरी और आंतरिक विवाद

उस समय से जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति हमेशा विवादग्रस्त एवं संघर्षयुक्त रही। इसके बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। आप पढ़ चुके हैं कि 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवाया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया।

Regional Aspirations

India claims that this area is under illegal occupation. Pakistan describes this area as 'Azad Kashmir'. Ever since 1947, Kashmir has remained a major issue of conflict between India and Pakistan.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

भारत ने दावा किया कि यह क्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को 'आज़ाद कश्मीर' कहा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है।

Regional Aspirations

Internally, there is a dispute about the status of Kashmir within the Indian union. You know that Kashmir was given a special status by Article 370 in our Constitution. You have studied about the special provisions under Articles 370 and 371 last year in Indian Constitution at Work. Article 370 gives greater autonomy to Jammu and Kashmir compared to other States of India. The State has its own Constitution.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर को संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। धारा 370 एवं 371 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में आपने पिछले वर्ष 'भारतीय संविधान : सिद्धांत और व्यवहार' में पढ़ा होगा। धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता दी गई है।

Regional Aspirations

All provisions of the Indian Constitution are not applicable to the State. Laws passed by the Parliament apply to J&K only if the State agrees.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएँ इस राज्य में लागू नहीं होती। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकते हैं।

Regional Aspirations

This special status has provoked two opposite reactions. There is a section of people outside of J&K that believes that the special status of the State conferred by Article 370 does not allow full integration of the State with India. This section feels that Article 370 should therefore be revoked and J&K should be like any other State in India.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस विशेष स्थिति से दो विरोधी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। लोगों का एक समूह मानता है कि इस राज्य को धारा 370 के तहत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है। यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए।

Regional Aspirations

Another section, mostly Kashmiris, believe that the autonomy conferred by Article 370 is not enough. A section of Kashmiris have expressed at least three major grievances. First, the promise that Accession would be referred to the people of the State after the situation created by tribal invasion was normalised, has not been fulfilled. This has generated the demand for a 'Plebiscite'. Secondly, there is a feeling that the special federal status guaranteed by Article 370, has been eroded in practice.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

दूसरा वर्ग (इसमें ज्यादातर कश्मीरी हैं) विश्वास करता है कि इतनी भर स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। कश्मीरियों के एक वर्ग ने तीन प्रमुख शिकायतें उठायी हैं। पहली यह कि भारत सरकार ने वायदा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत-संग्रह कराया जाएगा। इसे पूरा नहीं किया गया। दूसरी, धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दर्जा पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

This has led to the demand for restoration of autonomy or 'Greater State Autonomy'. Thirdly, it is felt that democracy which is practiced in the rest of India has not been similarly institutionalised in the State of Jammu and Kashmir.

इससे स्वायत्तता की बहाली अथवा राज्य को ज्यादा स्वायत्तता देने की माँग उठी। तीसरी शिकायत यह की जाती है कि भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है उस तरह का संस्थागत लोकतांत्रिक बरताव जम्मू-कश्मीर में नहीं होता।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Politics since 1948

After taking over as the Prime Minister, Sheikh Abdullah initiated major land reforms and other policies which benefited ordinary people. But there was a growing difference between him and the central government about his position on Kashmir's status. He was dismissed in 1953 and kept in detention for a number of years.

राजनीति : 1948 के बाद से

प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि-सुधार की बड़ी मुहिम चलायी। उन्होंने इसके साथ-साथ जन-कल्याण की कुछ नीतियाँ भी लागू कीं। इन सबसे यहाँ की जनता को फायदा हुआ। बहरहाल, कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र सरकार से मेल नहीं खाते थे। इससे दोनों के बीच मतभेद पैदा हुए। 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया। कई सालों तक उन्हें नज़रबंद रखा गया।

Regional Aspirations

The leadership that succeeded him did not enjoy as much popular support and was able to rule the State mainly due to the support of the Centre. There were serious allegations of malpractices and rigging in various elections.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता सत्तासीन हुए वे शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे। केंद्र के समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके। राज्य में हुए विभिन्न चुनावों में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

During most of the period between 1953 and 1974, the Congress party exercised a lot of influence on the politics of the State. A truncated National Conference (minus Sheikh Abdullah) remained in power with the active support of Congress for some time but later it merged with the Congress. Thus the Congress gained direct control over the government in the State. In the meanwhile, there were several attempts to reach an agreement between Sheikh Abdullah and the Government of India.

1953 से लेकर 1974 के बीच अधिकांश समय इस राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर रहा। कमज़ोर हो चुकी नेशनल कांफ्रेंस (शेख अब्दुल्ला के बिना) कांग्रेस के समर्थन से राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही लेकिन बाद में वह कांग्रेस में मिल गई। इस तरह राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी रही।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Finally, in 1974 Indira Gandhi reached an agreement with Sheikh Abdullah and he became the Chief Minister of the State. He revived the National Conference which was elected with a majority in the assembly elections held in 1977. Sheikh Abdullah died in 1982 and the leadership of the National Conference went to his son, Farooq Abdullah, who became the Chief Minister. But he was soon dismissed by the Governor and a breakaway faction of the National Conference came to power for a brief period.

आखिरकार 1974 में इंदिरा गाँधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस को फिर से खड़ा किया और 1977 के राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। सन् 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व की कमान उनके पुत्र फारुख अब्दुल्ला ने संभाली। फारुख अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। बहरहाल, राज्यपाल ने जल्दी ही उन्हें बर्खास्त कर दिया और नेशनल कांफ्रेंस से एक टूटे हुए गुट ने थोड़े समय के लिए राज्य की सत्ता संभाली।

Regional Aspirations

The dismissal of Farooq Abdullah's government due to the intervention of the Centre generated a feeling of resentment in Kashmir. The confidence that Kashmiris had developed in the democratic processes after the accord between Indira Gandhi and Sheikh Abdullah, received a set-back. The feeling that the Centre was intervening in politics of the State was further strengthened when the National Conference in 1986 agreed to have an electoral alliance with the Congress, the ruling party in the Centre.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूख अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया था। इससे कश्मीर में नाराज़गी के भाव पैदा हुए। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गाँधी के बीच हुए समझौते से राज्य के लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जमा था। फारूख अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी से इस विश्वास को धक्का लगा। 1986 में नेशनल कांग्रेस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। इससे भी लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है।

Regional Aspirations

Insurgency and after

It was in this environment that the 1987 Assembly election took place. The official results showed a massive victory for the National Conference - Congress alliance and Farooq Abdullah returned as Chief Minister. But it was widely believed that the results did not reflect popular choice, and that the entire election process was rigged. A popular resentment had already been brewing in the State against the inefficient administration since early 1980s.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

विद्रोही तेवर और उसके बाद

इसी माहौल में 1987 के विधानसभा चुनाव हुए। आधिकारिक नतीजे बता रहे थे कि नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली है। फारूख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। बहरहाल, लोग-बाग यह मान रहे थे कि चुनाव में धाँधली हुई है और चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। 1980 के दशक से ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष पनप रहा था।

Regional Aspirations

This was now augmented by the commonly prevailing feeling that democratic processes were being undermined at the behest of the Centre. This generated a political crisis in Kashmir which became severe with the rise of insurgency.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

लोगों के मन का गुस्सा यह सोचकर और भड़का कि केंद्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेरा-फेरी की जा रही है। इन सब बातों से कश्मीर में राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ। इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया।

Regional Aspirations

By 1989, the State had come in the grip of a militant movement mobilised around the cause of a separate Kashmiri nation. The insurgents got moral, material and military support from Pakistan. For a number of years the State was under President's rule and effectively under the control of the armed forces. Throughout the period from 1990, Jammu and Kashmir experienced violence at the hands of the insurgents and through army action.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

1989 तक यह राज्य उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया जा रहा था। उग्रवादियों को पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता दी। कई सालों तक इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राज्य पर सेना को नियंत्रण रखना पड़ा। 1990 से बाद के समय में इस राज्य के लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी।

Regional Aspirations

Assembly elections in the State were held only in 1996 in which the National Conference led by Farooq Abdullah came to power with a demand for regional autonomy for Jammu and Kashmir. J&K experienced a very fair election in 2002. The National Conference failed to win a majority and was replaced by People's Democratic Party (PDP) and Congress coalition government.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

1996 में एक बार फिर इस राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। फारुख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी और उसने जम्मू-कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँग की। जम्मू-कश्मीर में 2002 के चुनाव बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए। नेशनल कांफ्रेंस को बहुमत नहीं मिल पाया। इस चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस (PDP) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आई।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Separatism and beyond

Separatist politics which surfaced in Kashmir from 1989 has taken different forms and is made up of various strands. There is one strand of separatists who want a separate Kashmiri nation, independent of India and Pakistan. Then there are groups that want Kashmir to merge with Pakistan. Besides these, there is a third strand which wants greater autonomy for the people of the State within the Indian union.

अलगाववाद और उसके बाद

1989 से जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठाया था। इसने कई रूप लिए और इस राजनीति की कई धाराएँ हैं। अलगाववादियों का एक तबका कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है यानी एक ऐसा कश्मीर जो न पाकिस्तान का हिस्सा हो और न भारत का। कुछ अलगाववादी समूह चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। अलगाववादी राजनीति की एक तीसरी धारा भी है। इस धारा के समर्थक चाहते हैं कि कश्मीर भारत संघ का ही हिस्सा रहे लेकिन उसे और स्वायत्तता दी जाय।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

The idea of autonomy attracts the people of Jammu and Ladakh regions in a different way. They often complain of neglect and backwardness. Therefore, the demand for intra-State autonomy is as strong as the demand for the State autonomy.

स्वायत्तता की बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को अलग-अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की एक आम शिकायत उपेक्षा भरे बरताव और पिछड़ेपन को लेकर है। इस वजह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की माँग जितनी प्रबल है उतनी ही प्रबल माँग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी-अपनी स्वायत्तता को लेकर है।

Regional Aspirations

The initial period of popular support to militancy has now given way to the urge for peace. The Centre has started negotiations with various separatist groups. Instead of demanding a separate nation, most of the separatists in dialogue are trying to re-negotiate a relationship of the State with India.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

शुरुआती सालों में उग्रवाद को लोगों का कुछ समर्थन हासिल था लेकिन अब यहां के लोग शांति की कामना कर रहे हैं। केंद्र ने विभिन्न अलगाववादी समूहों से बातचीत शुरू कर दी है। अलग राष्ट्र की माँग की जगह अब अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्परिभाषित करने पर ज़ोर दे रहे हैं।

Regional Aspirations

Jammu and Kashmir is one of the living examples of plural society and politics. Not only are there diversities of all kind (religious, cultural, linguistic, ethnic, tribal) but there are also divergent political aspirations. However, despite all these diversities and divergence on the one hand, and the continued situation of conflict on the other, the plural and secular culture of the State has remained largely intact.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

जम्मू-कश्मीर बहुलवादी समाज और राजनीति का एक जीवन्त उदाहरण है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी, जातीय और जनजातीय यानी हर तरह की विभिन्नताएँ हैं। साथ ही, राजनीतिक आकांक्षाएँ भी एक-सी नहीं हैं। एक तरफ इस राज्य में विभिन्नताएँ और इसी के अनुकूल अलग-अलग राजनीतिक आकांक्षाएँ हैं तो दूसरी तरफ संघर्ष और तनाव की स्थितियाँ भी बदस्तूर कायम हैं। लेकिन, इन सबके बीच राज्य की बहुलतावादी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति अधिकांशतया अक्षुण्ण बनी हुई है।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Dravidian movement

‘Vadaku Vaazhkirathu; Therkku Thaeikirathu’ [The north thrives even as the south decays]. This popular slogan sums up the dominant sentiments of one of India’s most effective regional movements, the Dravidian movement, at one point of time. This was one of the first regional movements in Indian politics. Though some sections of this movement had ambitions of creating a Dravida nation, the movement did not take to arms.

द्रविड आंदोलन

‘उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन-दिन घटता जाए’ यह द्रविड आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है। यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालाँकि आंदोलन के नेतृवर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनायी।

Regional Aspirations

It used democratic means like public debates and the electoral platform to achieve its ends. This strategy paid off as the movement acquired political power in the State and also became influential at the national level. The Dravidian movement led to the formation of Dravidar Kazhagam [DK] under the leadership of Tamil social reformer E.V. Ramasami 'Periyar'.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

नेतृत्व ने अपनी माँग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ई. वी. रामास्वामी नायकर 'पेरियार' के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन—'द्रविड कषगम' का सूत्रपात हुआ।

Regional Aspirations

The organisation strongly opposed the Brahmins' dominance and affirmed regional pride against the political, economic and cultural domination of the North. Initially, the Dravidian movement spoke in terms of the whole of south India; however lack of support from other States limited the movement to Tamil Nadu. The DK split and the political legacy of the movement was transferred to Dravida Munnetra Kazhagam (DMK). The DMK made its entry into politics with a three pronged agitation in 1953-54.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और साँस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में, द्रविड आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे-धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। बाद में द्रविड कषगम दो धड़ों में बंट गया और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड मुनेत्र कषगम के पाले में केंद्रित हो गई। 1953-54 के दौरान डीएमके ने तीन-सूत्री आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की तीन माँगें थी :

Regional Aspirations

First, it demanded the restoration of the original name of Kallakudi railway station which had been renamed Dalmiapuram, after an industrial house from the North. This demand brought out its opposition to the North Indian economic and cultural symbols.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

पहली, कल्लाकुडी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम-डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह माँग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Punjab

The decade of 1980s also witnessed major developments in the State of Punjab. The social composition of the State changed first with Partition and later on after the carving out of Haryana and Himachal Pradesh. While the rest of the country was reorganised on linguistic lines in 1950s, Punjab had to wait till 1966 for the creation of a Punjabi speaking State.

पंजाब

1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालाँकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषायी आधार पर पुनर्गठित किया गया था लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतज़ार करना पड़ा। इस साल पंजाबी-भाषी प्रांत का निर्माण हुआ।

Regional Aspirations

The Akali Dal, which was formed in 1920 as the political wing of the Sikhs, had led the movement for the formation of a 'Punjabi suba'. The Sikhs were now a majority in the truncated State of Punjab.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने 'पंजाबी सूबा' के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी-भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Political context

After the reorganisation, the Akalis came to power in 1967 and then in 1977. On both the occasions it was a coalition government. The Akalis discovered that despite the redrawing of the boundaries, their political position remained precarious. Firstly, their government was dismissed by the Centre mid-way through its term.

राजनीतिक संदर्भ

पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनायी। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावांडोल है। पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था।

Regional Aspirations

Secondly, they did not enjoy strong support among the Hindus. Thirdly, the Sikh community, like all other religious communities, was internally differentiated on caste and class lines. The Congress got more support among the Dalits, whether Hindu or Sikh, than the Akalis.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बँटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच चाहे वे सिख हों या हिंदू—अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था।

Regional Aspirations

It was in this context that during the 1970s a section of Akalis began to demand political autonomy for the region. This was reflected in a resolution passed at their conference at Anandpur Sahib in 1973. The Anandpur Sahib Resolution asserted regional autonomy and wanted to redefine centre-state relationship in the country.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनज़र 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की माँग उठायी। 1973 में, आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठायी गई थी। प्रस्ताव की माँगों में केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी।

Regional Aspirations

The resolution also spoke of the aspirations of the Sikh qaum (community or nation) and declared its goal as attaining the bolbala (dominance or hegemony) of the Sikhs. The Resolution was a plea for strengthening federalism, but it could also be interpreted as a plea for a separate Sikh nation.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस प्रस्ताव में सिख 'कौम' (नेशन या समुदाय) की आकांक्षाओं पर ज़ोर देते हुए सिखों के 'बोलबाला' (प्रभुत्व या वर्चस्व) का एलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है। लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की माँग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।

Regional Aspirations

The Resolution had a limited appeal among the Sikh masses. A few years later, after the Akali government had been dismissed in 1980, the Akali Dal launched a movement on the question of the distribution of water between Punjab and its neighbouring States. A section of the religious leaders raised the question of autonomous Sikh identity. The more extreme elements started advocating secession from India and the creation of 'Khalistan'.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन-समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बँटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठायी। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर 'खालिस्तान' बनाने की वकालत की।

Regional Aspirations

Cycle of violence

Soon, the leadership of the movement passed from the moderate Akalis to the extremist elements and took the form of armed insurgency. These militants made their headquarters inside the Sikh holy shrine, the Golden Temple in Amritsar, and turned it into an armed fortress. In June 1984, the Government of India carried out 'Operation Blue Star', code name for army action in the Golden Temple.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

हिंसा का चक्र

जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्त्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्णमंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्णमंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' चलाया। यह स्वर्णमंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था।

Regional Aspirations

In this operation, the Government could successfully flush out the militants, but it also damaged the historic temple and deeply hurt the sentiments of the Sikhs. A large proportion of Sikhs in India and abroad saw the military operation as an attack on their faith and this gave further impetus to militant and extremist groups.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस सैन्य-अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्णमंदिर को क्षति भी पहुँची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य-अभियान को अपने धर्म-विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिला।

Regional Aspirations

Still more tragic turn of events complicated the Punjab problem further. Prime Minister Indira Gandhi was assassinated on 31 October 1984 outside her residence by her bodyguards. Both the assassins were Sikhs and wanted to take revenge for Operation Bluestar. While the entire country was shocked by this development, in Delhi and in many parts of northern India violence broke out against the Sikh community. The violence against the Sikhs continued for almost a week.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक-संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही।

Regional Aspirations

More than two thousand Sikhs were killed in the national capital, the area worst affected by this violence. Hundreds of Sikhs were killed in other parts of the country, especially in places like Kanpur, Bokaro and Chas. Many Sikh families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss. What hurt the Sikhs most was that the government took a long time in restoring normalcy and that the perpetrators of this violence were not effectively punished.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

दो हज़ार से ज्यादा की तादाद में सिख, दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख-परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुँचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही, हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Twenty years later, speaking in the Parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologised to the nation for the anti-Sikh violence.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख-विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी माँगी।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Road to peace

After coming to power following the election in 1984, the new Prime Minister Rajiv Gandhi initiated a dialogue with moderate Akali leaders. In July 1985, he reached an agreement with Harchand Singh Longowal, then the President of the Akali Dal. This agreement, known as the Rajiv Gandhi - Longowal Accord or the Punjab Accord, was a step towards bringing normalcy to Punjab.

शांति की ओर 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गाँधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

Regional Aspirations

It was agreed that Chandigarh would be transferred to Punjab, a separate commission would be appointed to resolve the border dispute between Punjab and Haryana, and a tribunal would be set up to decide the sharing of Ravi-Beas river water among Punjab, Haryana and Rajasthan. The agreement also provided for compensation to and better treatment of those affected by the militancy in Punjab and the withdrawal of the application of Armed Forces Special Powers Act in Punjab.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा-विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब-हरियाणा-राजस्थान के बीच रावी-व्यास के पानी के बँटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही, पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई।

Regional Aspirations

However, peace did not come easily or immediately. The cycle of violence continued nearly for a decade. Militancy and counter insurgency violence led to excesses by the police and violations of human rights. Politically, it led to fragmentation of the Akali Dal. The central government had to impose President's rule in the State and the normal electoral and political process was suspended.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

बहरहाल, पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद। हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही, पुलिस की ओर से भी ज्यादाती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

Regional Aspirations

It was not easy to restore the political process in the atmosphere of suspicion and violence. When elections were held in Punjab in 1992, only 24 per cent of the electors tuned out to vote.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24 फीसदी मतदाता वोट डालने के लिए आए।

Regional Aspirations

Militancy was eventually eradicated by the security forces. But the losses incurred by the people of Punjab – Sikhs and Hindus alike – were enormous. Peace returned to Punjab by the middle of 1990s. The alliance of Akali Dal (Badal) and the BJP scored a major victory in 1997, in the first normal elections in the State in the post-militancy era. The State is once again preoccupied with questions of economic development and social change. Though religious identities continue to be important for the people, politics has gradually moved back along secular lines.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हों या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल (बादल) और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालाँकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

The North-East

In the North-East, regional aspirations reached a turning point in 1980s. This region now consists of seven States, also referred to as the 'seven sisters'. The region has only 4 per cent of the country's population but about twice as much share of its area. A small corridor of about 22 kilometers connects the region to the rest of the country. Otherwise the region shares boundaries with China, Myanmar and Bangladesh and serves as India's gateway to South East Asia.

पूर्वोत्तर

पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ गई थीं। क्षेत्र में सात राज्य हैं और इन्हें 'सात बहनें' कहा जाता है। इस क्षेत्र में देश की कुल 4 फीसदी आबादी निवास करती है। लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली-सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है अन्यथा इस क्षेत्र की सीमाएँ चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं और यह इलाका भारत के लिए एक तरह से दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेश-द्वार है।

Regional Aspirations

The region has witnessed a lot of change since 1947. Tripura, Manipur and Khasi Hills of Meghalaya were erstwhile Princely States which merged with India after Independence. The entire region of North-East has undergone considerable political reorganisation. Nagaland State was created in 1963; Manipur, Tripura and Meghalaya in 1972 while Mizoram and Arunachal Pradesh became separate States only in 1987. The Partition of India in 1947 had reduced the North-East to a land locked region and affected its economy.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस इलाके में 1947 के बाद से अनेक बदलाव आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र, पहले अलग-अलग रियासत थे। आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। नगालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत-विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों से एकदम अलग-थलग पड़ गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Cut off from the rest of India, the region suffered neglect in developmental terms. Its politics too remained insulated. At the same time, most States in this region underwent major demographic changes due to influx of migrants from neighbouring States and countries.

भारत के शेष भागों से अलग-थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। यहाँ की राजनीति भी अपने ही दायरे में सीमित रही। इसके साथ-साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया।

Regional Aspirations

The isolation of the region, its complex social character and its backwardness compared to other parts of the country have all resulted in the complicated set of demands from different states of the North-East. The vast international border and weak communication between the North-East and the rest of India have further added to the delicate nature of politics there. Three issues dominate the politics of North-East: demands for autonomy, movements for secession, and opposition to 'outsiders'.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

पूर्वोत्तर का अलग-थलग पड जाना, इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, जैसी कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की माँगें उठीं। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफी बड़ी है लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संचार-व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर तीन मुद्दे हावी हैं: स्वायत्तता की माँग, अलगाव के आंदोलन और 'बाहरी' लोगों का विरोध।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Major initiatives on the first issue in the 1970s set the stage for some dramatic developments on the second and the third in the 1980s.

इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की माँग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी। इससे शेष दो मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ लिया।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Demands for autonomy

At independence the entire region except Manipur and Tripura comprised the State of Assam. Demands for political autonomy arose when the non-Assamese felt that the Assam government was imposing Assamese language on them. There were opposition and protest riots throughout the State. Leaders of the major tribal communities wanted to separate from Assam.

स्वायत्तता की माँग

आजादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था। गैर-असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की माँग उठी। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे।

Regional Aspirations

They formed the Eastern India Tribal Union which later transformed into a more comprehensive All Party Hill Leaders Conference in 1960. They demanded a tribal State to be carved out of Assam. Finally instead of one tribal State, several States got carved out of Assam. At different points of time the Central Government had to create Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh out of Assam. Tripura and Manipur were upgraded into States too.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इन लोगों ने 'ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन' का गठन किया जो 1960 में कहीं ज्यादा व्यापक 'ऑल पार्टी हिल्स कांफ्रेंस' में तब्दील हो गया। इन नेताओं की माँग थी कि असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक जनजातीय राज्य की जगह असम को काटकर कई जनजातीय राज्य बने। केंद्र सरकार ने अलग-थलग वक्त पर असम को बाँटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया।

Regional Aspirations

The reorganisation of the North-East was completed by 1972. But this was not the end of autonomy demands in this region. In Assam, for example, communities like the Bodos, Karbis and Dimasas wanted separate States. They worked for this demand by mobilising public opinion and popular movement as well as through insurgency. Often the same area was claimed by more than one community.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था। लेकिन, स्वायत्तता की माँग खत्म न हुई। उदाहरण के लिए, असम के बोडो, करबी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की माँग की। अपनी माँग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए और विद्रोही कार्रवाइयाँ भी कीं। कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जतायी।

Regional Aspirations

It was not possible to go on making smaller and yet smaller States. Therefore, some other provisions of our federal set up were used to satisfy their autonomy demands while remaining in Assam. Karbis and Dimasas have been granted autonomy under District Councils while Bodos were recently granted Autonomous Council.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

छोटे-छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। इस वजह से संघीय राजव्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की माँग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया। करबी और दिमसा समुदायों को जिला-परिषद् के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद् का दर्जा दिया गया है।

Regional Aspirations

Secessionist movements

Demands for autonomy were easier to respond to, for these involved using the various provisions in the Constitution for accommodation of diversities. It was much more difficult when some groups demanded a separate country, not in momentary anger but consistently as a principled position. The country's leadership faced this problem for a very long time in at least two States in the North-East. A comparison of these two cases offers us a lesson in democratic politics.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

अलगाववादी आंदोलन

स्वायत्तता की माँगों से निपटना आसान था क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद थे। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की माँग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस माँग से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के दो राज्यों में अलगाववादी माँग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन दो मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है।

Regional Aspirations

After Independence, the Mizo Hills area was made an autonomous district within Assam. Some Mizos believed that they were never a part of British India and therefore did not belong to the Indian union. But the movement for secession gained popular support after the Assam government failed to respond adequately to the great famine of 1959 in Mizo hills. The Mizos' anger led to the formation of the Mizo National Front (MNF) under the leadership of Laldenga.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्त जिला बना दिया गया था। कुछ मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी भी 'ब्रिटिश इंडिया' के अंग नहीं रहे इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय इलाके में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जनसमर्थन मिलना शुरू हुआ। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लालडेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया।

Regional Aspirations

In 1966 the MNF started an armed campaign for independence. Thus, started a two decade long battle between Mizo insurgents and the Indian army. The MNF fought a guerilla war, got support from Pakistani government and secured shelter in the then East Pakistan. The Indian security forces countered it with a series of repressive measures of which the common people were the victims. At one point even Air Force was used. These measures caused more anger and alienation among the people.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी की माँग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच दो दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक दफ़े तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई।

Regional Aspirations

At the end of two decades of insurgency everyone was a loser. This is where maturity of the political leadership at both ends made a difference. Laldenga came back from exile in Pakistan and started negotiations with the Indian government. Rajiv Gandhi steered these negotiations to a positive conclusion. In 1986 a peace agreement was signed between Rajiv Gandhi and Laldenga. As per this accord Mizoram was granted full-fledged statehood with special powers and the MNF agreed to give up secessionist struggle.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

दो दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। इसी बात को भाँपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लालडेंगा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गाँधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुँचाया। 1986 में राजीव गाँधी और लालडेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया।

Regional Aspirations

Laldenga took over as the Chief Minister. This accord proved a turning point in the history of Mizoram. Today, Mizoram is one of the most peaceful places in the region and has taken big strides in literacy and development.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

लालडेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है।

Regional Aspirations

The story of Nagaland is similar to Mizoram, except that it started much earlier and has not yet had such a happy ending. Led by Angami Zaphu Phizo, a section of the Nagas declared independence from India way back in 1951. Phizo turned down many offers of negotiated settlement. The Naga National Council launched an armed struggle for sovereignty of Nagas. After a period of violent insurgency a section of the Nagas signed an agreement with the Government of India but this was not acceptable to other rebels. The problem in Nagaland still awaits a final resolution.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

नगालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह है लेकिन नगालैंड का अलगावादी आंदोलन ज्यादा पुराना है और अभी इसका मिजोरम की तरह खुशगवार हल नहीं निकल पाया है। अंगमी जापू पि फ़िजो के नेतृत्व में नगा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित कर दिया था। फ़िजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह के एक दौर के बाद नगा लोगों के एक तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नगालैंड की समस्या का समाधान होना अब भी बाकी है।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Movements against outsiders

The large scale migration into the North-East gave rise to a special kind of problem that pitted the 'local' communities against people who were seen as 'outsiders' or migrants. These latecomers, either from India or abroad are seen as encroachers on scarce resources like land and potential competitors to employment opportunities and political power. This issue has taken political and sometimes violent form in many States of the North-East.

बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन

पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासी आए हैं। इससे एक खास समस्या पैदा हुई है। स्थानीय जनता इन्हें 'बाहरी' समझती है और 'बाहरी' लोगों के खिलाफ उसके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्यों अथवा किसी अन्य देश से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के अवसरों और राजनीतिक सत्ता के एतबार से एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती है। स्थानीय लोग बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले ने राजनीतिक रंग ले लिया है और कभी-कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएँ भी होती हैं।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

The Assam Movement from 1979 to 1985 is the best example of such movements against 'outsiders'. The Assamese suspected that there were huge numbers of illegal Bengali Muslim settlers from Bangladesh. They felt that unless these foreign nationals are detected and deported they would reduce the indigenous Assamese into a minority. There were other economic issues too.

1979 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत-सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशी लोगों को पहचानकर उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। कुछ आर्थिक मसले भी थे।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

There was widespread poverty and unemployment in Assam despite the existence of natural resources like oil, tea and coal. It was felt that these were drained out of the State without any commensurate benefit to the people.

असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी। यहां की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

In 1979 the All Assam Students' Union (AASU), a students' group not affiliated to any party, led an anti-foreigner movement. The movement was against illegal migrations, against domination of Bengalis and other outsiders, and against faulty voters' register that included the names of lakhs of immigrants. The movement demanded that all outsiders who had entered the State after 1951 should be sent back. The agitation followed many novel methods and mobilised all sections of Assamese people, drawing support across the State.

1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू-AASU) ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। 'आसू' एक छात्र-संगठन था और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। 'आसू' का आंदोलन अवैध आप्रवासी, बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों आप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ़ था। आंदोलन की माँग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। इस आंदोलन ने कई नए तरीकों को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया। इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

It also involved many tragic and violent incidents leading to loss of property and human lives. The movement also tried to blockade the movement of trains and the supply of oil from Assam to refineries in Bihar.

आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएँ भी हुईं। बहुत-से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन-संपत्ति का नुकसान हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बिहार स्थित बरौनी तेलशोधक कारखाने को तेल-आपूर्ति रोकने की भी कोशिश की गई।

Regional Aspirations

Eventually after six years of turmoil, the Rajiv Gandhi-led government entered into negotiations with the AASU leaders, leading to the signing of an accord in 1985. According to this agreement those foreigners who migrated into Assam during and after Bangladesh war and since, were to be identified and deported. With the successful completion of the movement, the AASU and the Asom Gana Sangram Parishad organised themselves as a regional political party called Asom Gana Parishad (AGP).

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

छह साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गाँधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 'आसू' के नेताओं से बातचीत शुरू की। इसके परिणामस्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश-युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद 'आसू' और असम गण संग्राम परिषद् ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया। इस पार्टी का नाम 'असम गण परिषद्' रखा गया।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

It came to power in 1985 with the promise of resolving the foreign national problem as well as to build a 'Golden Assam'.

असम गण परिषद् 1985 में इस वायदे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा और एक 'स्वर्णिम असम' का निर्माण किया जाएगा।

Regional Aspirations

Assam accord brought peace and changed the face of politics in Assam, but it did not solve the problem of immigration. The issue of the 'outsiders' continues to be a live issue in the politics of Assam and many other places in the North-East. This problem is particularly acute, for example, in Tripura as the original inhabitants have been reduced to being a minority in their own land. The same feeling informs the hostility of the local population to Chakma refugees in Mizoram and Arunachal Pradesh.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

असम-समझौते से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला लेकिन 'आप्रवास' की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। 'बाहरी' का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की, राजनीति में एक जीवंत मसला है। यह समस्या त्रिपुरा में ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां के मूल निवासी खुद अपने ही प्रदेश में अल्पसंख्यक बन गए हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा है।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

Accommodation and National Integration

These cases have shown us that even after six decades of Independence, some of the issues of national integration are not fully resolved. We have seen that regional aspirations ranging from demands of statehood and economic development to autonomy and separation keep coming up. The period since 1980 accentuated these tensions and tested the capacity of democratic politics to accommodate the demands of diverse sections of the society. What lessons can we draw from these examples?

समाहार और राष्ट्रीय अखंडता

इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के छह दशक बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लगातार एक न एक रूप में उभरती रहीं। कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की माँग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठा। कहीं-कहीं से अलगाववाद के स्वर उभरे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की माँगों में पटरी बैठा पाने की लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

First and the most elementary lesson is that regional aspirations are very much a part of democratic politics. Expression of regional issues is not an aberration or an abnormal phenomenon. Even in smaller countries like the United Kingdom there are regional aspirations in Scotland, Wales and Northern Ireland. Spain faces secessionist movement from the Basques and so does Sri Lanka from the Tamils. A large and diverse democracy like India must deal with regional aspirations on a regular basis. Nation building is an ongoing process

पहला और बुनियादी सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएँ लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएँ उभरी हैं। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी माँग की। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएँ भी बड़े पैमाने पर हैं। अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होगी।

Regional Aspirations

The second lesson is that the best way to respond to regional aspirations is through democratic negotiations rather than through suppression. Look at the situation in the eighties – militancy had erupted in Punjab; problems were persisting in the North-East; students in Assam were agitating; Kashmir valley was on the boil. Instead of treating these as simple law and order problems, the Government of India reached negotiated settlement with regional movements.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। जरा अस्सी के दशक की तरफ़ नज़र दौड़ाएँ—पंजाब में उग्रवाद का जोर था; पूर्वोत्तर में समस्याएँ बनी हुई थीं; असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। इन मसलों को सरकार ने कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

This produced a reconciliation which reduced the tensions existing in many regions. The example of Mizoram shows how political settlement can resolve the problem of separatism effectively.

इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव कम हुआ। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

The third lesson is about the significance of power sharing. It is not sufficient to have a formal democratic structure. Besides that, groups and parties from the region need to be given share in power at the State level. Similarly, it is not sufficient to say that the states or the regions have autonomy in their matters. The regions together form the nation. So, the regions must have a share in deciding the destiny of the nation. If regions are not given a share in the national level decision making, the feeling of injustice and alienation can spread.

तीसरा सबक है सत्ता की साझदारी के महत्त्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढाँचा खड़ा कर लेना ही काफी नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राजव्यवस्था में हिस्सेदार बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह यह कहना भी नाक़फी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा।

Regional Aspirations

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

The fourth lesson is that regional imbalance in economic development contributes to the feeling of regional discrimination. Regional imbalance is a fact of India's development experience. Naturally, the backward states or backward regions in some states feel that their backwardness should be addressed on priority basis and that the policies of the Indian government have caused this imbalance. If some states remain poor and others develop rapidly, it leads to regional imbalances and inter-regional migrations.

चौथा सबक यह है कि आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियाँ अपनायी हैं उसी के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहें और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। साथ ही, अंतर्प्रान्तीय अथवा अंतर्क्षेत्रीय आप्रवास में भी बढ़ोत्तरी होगी।

Regional Aspirations

Finally, these cases make us appreciate the farsightedness of the makers of our Constitution in dealing with questions of diversity. The federal system adopted by India is a flexible arrangement. While most of the states have equal powers, there are special provisions for some states like J&K and the states in the North-East. The Sixth Schedule of the Constitution allows different tribes complete autonomy of preserving their practices and customary laws. These provisions proved crucial in resolving some very complex political problems in the North-East.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

सबसे आखिरी बात यह कि इन मामलों से हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का पता चलता है। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे। हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं। भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनायी है वह बहुत लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं तो जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की छठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार-व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए।

Regional Aspirations

What distinguishes India from many other countries that face similar challenges is that the constitutional framework in India is much more flexible and accommodative. Therefore, regional aspirations are not encouraged to espouse separatism. Thus, politics in India has succeeded in accepting regionalism as part and parcel of democratic politics.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

भारत का संवैधानिक ढाँचा ज्यादा लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह की चुनौतियाँ भारत में पेश आयीं वैसी कुछ दूसरे देशों में भी आयी लेकिन भारत का संवैधानिक ढाँचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहां अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया है कि क्षेत्रीयता, लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है।

Regional Aspirations

Sikkim's merger

At the time of Independence, Sikkim was a 'protectorate' of India. It meant that while it was not a part of India, it was also not a fully sovereign country. Sikkim's defence and foreign relations were looked after by India, while the power of internal administration was with the Chogyal, Sikkim's monarch. This arrangement ran into difficulty as the Chogyal was unable to deal with the democratic aspirations of the people. An overwhelming majority of Sikkim's population was Nepali.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

सिक्किम का विलय

आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की 'शरणागति' प्राप्त थी। इसका मतलब यह कि तब सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था लेकिन वह पूरी तरह संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहां के राजा चोग्याल के हाथों में थी। यह व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो पायी क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके। सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था।

Regional Aspirations

But the Chogyal was seen as perpetuating the rule of a small elite from the minority Lepcha-Bhutia community. The anti-Chogyal leaders of both the communities sought and got support from the Government of India.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चोग्याल अल्पसंख्यक लेपचा-भूटिया के एक छोटे-से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चोग्याल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद माँगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया।

Regional Aspirations

The first democratic elections to Sikkim assembly in 1974 were swept by Sikkim Congress which stood for greater integration with India. The assembly first sought the status of 'associate state' and then in April 1975 passed a resolution asking for full integration with India. This was followed by a hurriedly organised referendum that put a stamp of popular approval on the assembly's request. The Indian Parliament accepted this request immediately and Sikkim became the 22nd State of the Indian union.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी। सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के 'सह-प्रान्त' बनने की कोशिश की और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम के पूर्ण विलय की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत-संग्रह कराया गया और जनमत-संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया और सिक्किम भारत का 22वाँ राज्य बन गया।

Regional Aspirations

Chogyal did not accept this merger and his supporters accused the Government of India of foul play and use of force. Yet the merger enjoyed popular support and did not become a divisive issue in Sikkim's politics.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

चोग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल-प्रयोग करने का आरोप लगाया। बहरहाल, भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा न बन सका!

Regional Aspirations

Goa's liberation

Although the British empire in India came to an end in 1947, Portugal refused to withdraw from the territories of Goa, Diu and Daman which were under its colonial rule since the sixteenth century. During their long rule, the Portuguese suppressed the people of Goa, denied them civil rights, and carried out forced religious conversions. After India's Independence, the Indian government tried very patiently to persuade the Portuguese government to withdraw.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

गोवा की मुक्ति

हालाँकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। यह क्षेत्र सोलहवीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था। अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था। उसने यहाँ के लोगों को नागरिकों अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म-परिवर्तन कराया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्यपूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंद करने की कोशिश की।

Regional Aspirations

There was also a strong popular movement within Goa for freedom. They were strengthened by socialist satyagrahis from Maharashtra. Finally, in December 1961, the Government of India sent the army which liberated these territories after barely two days of action. Goa, Diu and Daman became Union Territory.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

गोवा में आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला। इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। आखिरकार, दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी। दो दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और दीव संघशासित प्रदेश।

Regional Aspirations

Another complication arose soon. Led by the Maharashtrawadi Gomanatak Party (MGP) one section desired that Goa, as a Marathi speaking area should merge with Maharashtra. However, many Goans were keen to retain a separate Goan identity and culture, particularly the Konkani language. They were led by the United Goan Party (UGP). In January 1967, the Central Government held a special 'opinion poll' in Goa asking people to decide if they wanted to be part of Maharashtra or remain separate.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

जल्दी ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने माँग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए क्योंकि यह मराठी-भाषी क्षेत्र है। बहरहाल, बहुत-से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोअन पार्टी (**UGP**) ने किया। 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं।

Regional Aspirations

A referendum-like procedure was used to ascertain people's wishes on this issue. The majority voted in favour of remaining outside of Maharashtra. Thus, Goa continued as a Union Territory. Finally, in 1987, Goa became a State of the Indian Union.

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत-संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनायी थी। अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघशासित प्रदेश बना रहा। अंततः 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना।